हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 62 देहरादून, मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

मध्य क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक उत्तराखण्ड में आयोजित करने का सीएम धामी ने दिया प्रस्ताव 3

आदर्श चम्पावत उत्तराखण्ड / 25 के मंथन में निकले कई ठोस सुझाव

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 22 अगस्त। उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन (हैस्को) देहरादून के सहयोग से आदर्श चम्पावत उत्तराखण्ड/25 पर विचार मंथन का आयोजन यूकॉस्ट के विज्ञान धाम परिसर, झाजरा में आयोजित किया गया।

हिमालय की पारिस्थितिकीय विभिन्नता के दृष्टिगत अलग अलग मुद्दो पर विभिन्न प्रयोग करने का हमारे लिए एक अवसर है। उन्होंने हाल ही में बांदल घाटी में हुई आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह कि घटनाओ की पुनरावृति एक चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि आदर्श चम्पावत के मॉडल के जरिये पूरे हिमालय के लिए विकास नीति की नींव रखे जाने का यह एक अच्छा अवसर है। इसके माध्यम से हम अन्य हिमालयी राज्यों को पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल नीति और विकास की दिशा दे पाएंगे, यह कहना है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन (हैस्को) देहरादून के संरक्षक पद्मभूषण, डा0 अनिल जोशी का। साथ ही यह भी कहा कि समाज, सरकार एवं गैर सरकारी संस्थान को मिलकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य का विकास पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुये कार्ययोजना तैयार करनी होगी जिसमें हैस्को सहयोग कर सकता है।

प्रो0 दुर्गेश पंत, महानिदेशक, द्वारा सभी विभागों का स्वागत करते हुये कहा कि

मुख्यमंत्री की एक अभिनव पहल है बोधिसत्व विचार श्रृंखला। इस विचार मंथन से जल, जंगल, जमीन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रो में कार्य कर रहे सरकारी तथा गैर-सरकारी विषय विशेषज्ञों के बीच विचारों का मंथन होता है। बोधिसत्व विचार श्रृंखला से राज्य के सतत विकास लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज प्राप्त हो रहे हैं और इसी कड़ी में आदर्श चम्पावत उत्तराखण्ड/25 के विजन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं।

सरकार के विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स तथा गैर-सरकारी संस्थानों से आये विभिन्न विषय विशेषज्ञ तथा अधिकारीगण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से चम्पावत को आदर्श जनपद के रुप में विकसित करने हेतु विचार मंथन करेंगे। इस हेतु सभी विभाग आपस में मिलकर विकास कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाते हुए सीएम पुष्कर सिह धामी के उत्तराखण्ड/25 के लक्ष्य को धरातल पर उतारने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चम्पावत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आदर्श जनपद बनाने हेतु परिषद को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। परिषद को विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर चम्पावत को आदर्श जनपद बनाने का कार्य करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से भूमि एवं जल संसाधनों में सुधार, कृषि व बागवानी एवं इन पर आधारित उद्योग, वैल्यू एडिशन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा तथा विभिन्न क्षेत्रो में महती भूमिका निभाकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन बन सकते हैं।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव, डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम (आई0ए0एस0) द्वारा बताया गया कि चम्पावत जनपद का सर्वे और अध्ययन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ताकि एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जा सके। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोगों को राज्य से बाहर जाना पड़ता है जबकि यहीं पर रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते है।

उन्होंने कहा इस विचार मंथन सत्र का उद्देश्य जनपद में आजीविका सृजन के अवसर तलाशना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कि सहायता से लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य आधारित योजनायें बनायीं जाए जैसे - कैटल ब्रीडिंग हब, दुग्ध मूल्य संवर्धन, बागवानी, फूलों की खेती, स्थानीय मसालें, होम स्टे योजना के तहत स्थानीय लोगों का कौशल विकास आदि पर विशेष ध्यान देने कि बात कही।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पुलों की नियमित जाँच के दिए सख्त आदेश

लोनिवि व सिंचाई विभाग के अधिकारी नियमित करें पुलों की निगरानी : महाराज

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश के पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों ने सहायता पहुंचाने के साथ-साथ खाद्यान सामग्री भी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अतिवृष्टि के चलते मालदेवता, बांदल घाटी स्थित सरखेत और यमकेश्वर सहित अन्य स्थानों पर हुई जानमाल की क्षति चिंता जाहिर करते हुए लोक निर्माण विभाग के एचओडी अयाज अहमद और सिंचाई विभाग के एचओडी को निर्देश दिए हैं कि जितने भी पुल हैं उनका लगातार निरीक्षण किया जाए। महाराज ने जिलाधिकारी पौड़ी से वार्ता कर निर्देश दिए कि यमकेश्वर के प्रभावित क्षेत्रों में लेखपाल को भेजकर रिपोर्ट तैयार करवाई जाए ताकि लोगों को आंशिक सहायता के साथ-साथ खाद्यान्न पहुंचाया जा सके।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि वह शीघ्र ही इस संबंध में पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेंगे जिसमें नदियों के चैनेलाइजेशन के विषय में भी कहा जाएगा।

आयुक्त सुशील कुमार ने आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने के दिये निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । आयुक्त गढवाल मण्डल सुशील कुमार ने गढवाल मण्डल क्षेत्रान्तर्गत जनपद देहरादून, टिहरी, एवं पौड़ी गढवाल में शुक्रवार रात्रि हुई अतिवृष्टि में हुए नुकसान के सम्बन्ध में नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। खोजबीन/सर्च कार्य जारी है। आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 04 जनहानि हुई है। गढ़वाल मण्डल में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनमें से टिहरी जनपद में 02 तथा देहरादून जनपद में 01 एवं पौड़ी जनपद में 01 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जबकि 14 लोग लापता हैं। जनपद टिहरी से 7 तथा जनपद देहरादून से 7 लोग लापता है। लापता लोगों की खोजबीन का कार्य गतिमान है।

पैदल मार्ग, पेयजल लाइन एवं एक अमृत सरोवर तथा राजकीय संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जिनका आकलन राजस्व विभाग के टीम द्वारा किया जा रहा है। गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान व सम्पत्ति पुर्ननिर्माण अनुदान के संबंध में जांच कर प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के संबंध

में कार्यवाही की जा रही है। एक राजकीय हेलीकाप्टर बचाव कार्य में तैनात है। एन०डी०आर०एफ० के 39 एस०डी०आर०एफ० 64 जवानों के अलावा पुलिस, राजस्व व स्वास्थ्य विभाग की टीमें बचाव व राहत कार्यों में लगी हैं। आपदा से हुई कृषि नुकसान का आकलन करने हेतु राजस्व की टीम लगाई गई है।

काम की बात : क्या आपको भी फटाफट कैश देने की आदत है तो सावधान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त ।हॉस्पिटल, बैंक्वेट हॉल और बिजनेस में कैश अधिक खर्च किया जाए और उसे टैक्स रिटर्न फाइल में नहीं दिखाया जाए तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के आधार पर टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है.हर काम में फटाफट कैश देने की आदत है ? ऑनलाइन पेमेंट से आपको हिचक है ? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाएं. कैश में बड़ा खर्च करते हैं, तो सावधान रहने की जरूरत है. टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स विभाग अपनी निगरानी तेज कर चुका है. अगर आप अस्पताल, बैंक्वेट हॉल और बिजनेस में कैश में बड़ी रकम खर्च करते हैं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है. टैक्स विभाग के मुताबिक कुछ कैश ट्रांजैक्शन वैध नहीं होते हैं और इस तरह के खर्च आपको नोटिस भी दिला सकते हैं. लोन या डिपॉजिट के रूप में 20,000 रुपये या इससे अधिक लेना मना है. इस तरह के ट्रांजैक्शन किसी बैंकिंग चैनल के तहत ही होने चाहिए.

नियम यह भी कहता है कि किसी से कैश में एकमुश्त 2 लाख या इससे अधिक नहीं ले सकते. टैक्स डिडक्शन के नजरिये से किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या राजनीतिक पार्टी को कैश में दान देना भी मना है. ऐसा कोई करता है तो वह मुसीबत में फंस सकता है. इन नियमों का पालन कराने के लिए टैक्स विभाग कुछ बिजनेस और पेशे से जुड़े कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है. इसमें हॉस्पिटल का खर्च भी शामिल है.

क्या है इनकम टैक्स का नियम

इनकम टैक्स से जुड़ा नियम कहता है कि हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट जैसे कि हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में मरीज भर्ती होता है, तो उससे पैन की डिटेल ली जानी चाहिए. हालांकि हॉस्पिटल इस नियम की अवहेलना करते हैं. ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है. रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स विभाग हॉस्पिटल से वैसे मरीजों की जानकारी जुटाएगा, उन मरीजों को ट्रैक करेगा जो प्राइवेट अस्पतालों या नर्सिंग होम में इलाज पर भारी कैश खर्च करते हैं. इसके लिए मरीजों के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है ताकि रिटर्न फाइलिंग की गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके.

कैसे बच सकते हैं कार्रवाई से

टैक्स विभाग के नोटिस या कार्रवाई से बचना है तो आईटीआर में वही जानकारी दी जानी चाहिए जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्सपेयर इनफॉर्मेशन सम्मरी में दर्ज हो. हॉस्पिटल, बेंक्वेट हॉल और बिजनेस में कैश अधिक खर्च किया जाए और उसे टैक्स रिटर्न फाइल में नहीं दिखाया जाए तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. अगर टैक्स विभाग एआईएस और टीआईएस की जानकारी के आधार पर टैक्स रिटर्न को मिलान करे और उसमें गड़बड़ी दिख जाए तो टैक्सपेयर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है. इस कार्रवाई से बचने के लिए कैश में खर्च न कर, किसी बैंकिंग चैनल या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट किया जाना चाहिए.

क्या आप भी एस्केलेटर ब्रश पर जूते साफ करते है ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । क्या आप भी अपने जूते एस्केलेटर ब्रश से साफ करते हैं? आपने एस्केलेटर के किनारे लगे ब्रश से लोगों को अपने जूते साफ करते देखा होगा और आपने भी कहा होगा कि यह ब्रश इसलिए ही होता है। लेकिन नहीं ये ब्रेसेस जूतों को साफ करने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए हैं। कैसे? आइए बताते है आपको।

लोग बिना जाने अफवाह फैला देते हैं और वह अफवाह ऐसे ही उड़ती रहती है और लोग उसे सच मानकर बैठ जाते हैं, यह जानने की कोशिश तक नहीं करते कि यह सच है या नहीं। एक ऐसे हे अफवा एस्केलेटर के किनारे लगे ब्रश की है। हम सभी ने एस्केलेटर के किनारे लगे ब्रशों को देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रश क्यों होते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये ब्रश सिर्फ डिजाइन के लिए हैं या आप इन ब्रशों का इस्तेमाल जूतों को साफ करने के लिए कर सकते हैं तो आप गलत हैं। एस्केलेटर के किनारे के ब्रश आपके जूते साफ करने के लिए नहीं होते हैं। आपको बता दें कि ये ब्रश आपकी सुरक्षा के लिए हैं।दरअसल एस्केलेटर पर लगे ये ब्रश साइड और दीवार के बीच के गैप को छिपाने का काम करते हैं।

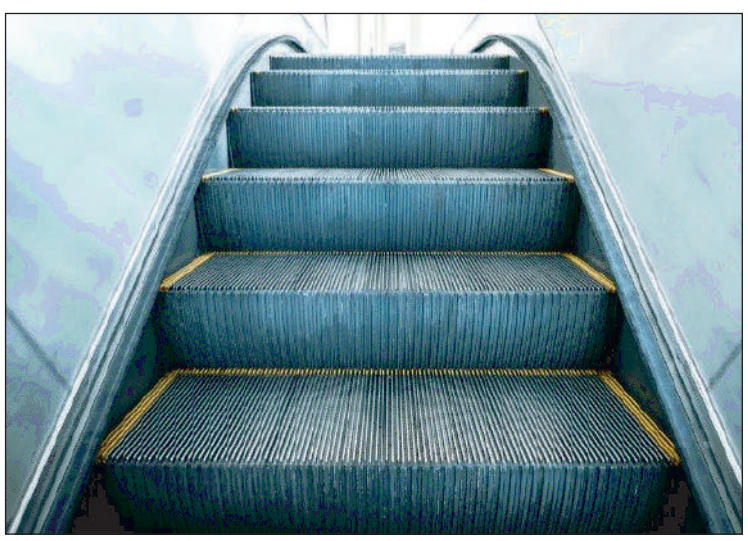

ये ब्रश इसलिए हैं ताकि जूते के फीते या स्कार्फ जैसी छोटी-छोटी चीजें इस गैप के अंदर न जाएं। अगर ये सारी चीजें एस्केलेटर्स पर अटक जाती हैं तो ये मशीन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ब्रश लगाया जाता है। ऐसे में अगर आपके हाथ या जेब से कोई छोटी सी चीज गिर भी जाए तो भी वह इन गैप्स में नहीं जाकर ब्रश से डायवर्ट कर सीढ़ियों पर ही रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एस्केलेटर के किनारे पर आ जाता है तो वह पैर फंसने से चोटिल होने से बचाने में मदद करता है। ऐसे में ये आपको हादसों से बचाने का भी काम करते हैं।

33वे राष्ट्रीय कैनो सप्रिंट सीनियर (महिला एवम पुरुष) चैम्पियनशिप का शुभारंभ हुआ

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

गदरपुर, 22 अगस्त। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभाग करने पहुंचे प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर, सभी का अभिवादन किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौंसला अफजाई करते हुए कहा कि खेलों में जो जीत नहीं पाएंगे, वह कतई निराश न हों, बल्कि अपनी कमियों को चिन्हित करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए स्वयं को और अधिक जज्बे व जानून के साथ तैयार करें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और हार शब्द का प्रयोग न करें। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य में इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन होना, राज्य व इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि राज्य में बौर जलाशय -नानकमत्ता जलाशय व संजय वन को जोड़ते हुए सर्किट बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश वन विभाग तथा जिला प्रशासन को दिए। गए हैं। इंडियन कयाकिंग, केनोइंग एसोसिएशन के संरक्षक बलवीर सिंह कुशवाहा ने कहा कि भविष्य में बौर जलाशय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएंगी और उत्तराखंड को तकनीकी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने भी अपने विचार रखे।

केंद्रीय मंत्री तथा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की प्रशंसा की। 1000 मीटर में k-1,k-2,k-4 तथा C-1, C-2,C-4 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इस दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एससी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक संघ, महासचिव इंडियन क्योस्क, केनोइंग एसोसिएशन डीके बरार, तकनीकी अधिकारी रामा कृष्ण, मयंक ठाकुर, जिलाध्यक्ष विवेक सक्सैना, जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग सहित प्रतिभागी, स्थानीय जनता आदि उपस्थित थी।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक उत्तराखण्ड में आयोजित करने का सीएम धामी ने दिया प्रस्ताव

सीएम धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23 वीं बैठक में राज्य के विकास का दिया ब्यौरा

मो० सलीम सैफ़ी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23 वीं बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण हेतु एक विशेष अभियान प्रारम्भ किये जाने और राज्यों के मध्य संसाधनों के आवंटन में इको सिस्टम सेवाओं को महत्ता दिये जाने और केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के आवंटन में फ्लोटिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखे जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में एक सशक्त वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, डॉप्लर रडार से युक्त अवस्थापना तंत्र के लिये सहयोग किये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक देवभूमि उत्तराखण्ड में आयोजित करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास में मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिये आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण, पावन बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर गतिमान है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र पोषित योजनाओं के निर्धारण में राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वन स्किम फिट ऑल के स्थान पर राज्य के अनुकूल टेलर मेड स्कीम तैयार करने पर भारत सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यटन, हार्टीकल्चर तथा सगन्ध पौध आधारित केन्द्रीय योजनाओं से राज्य को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने बरसाती नदियों को वैज्ञानिक आधार से ग्लेशियर आधारित नदियों से जोड़े जाने का सुझाव देते हुए कहा कि इसका लाभ उत्तराखण्ड राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को होगा। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण हेतु एक विशेष अभियान को भी प्रारम्भ किये जाने का सुझाव दिया। उन्होंने उत्तराखण्ड की बाधित जल विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से सहयोग का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य अपने वनों, बुग्यालों, ग्लेशियरों का संरक्षण करके राष्ट्र को महत्वपूर्ण इको सिस्टम सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। भोपाल के ही प्रतिष्ठित भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार इन पारिस्थितिकी सेवाओं का वार्षिक मूल्य न्यूनतम रू. 95,000 करोड़ आंका गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यों के मध्य संसाधनों के आवंटन में इन पारिस्थितिकी सेवाओं को महत्ता दिये का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश-विदेश से बहुत अधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों का आवागमन राज्य में होता है। उत्तराखण्ड की जनसंख्या लगभग सवा करोड़ है किन्तु प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड में लगभग छः करोड़ लोगों का फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में आगमन होता है। इस प्रकार राज्य सरकार को लगभग सवा सात करोड़ लोगों हेतु अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के आवंटन में फ्लोटिंग पॉपुलेशन के इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के सीमान्त क्षेत्रों को सड़क, रेलवे व वायु मार्ग से जोड़ना अत्यावश्यक है। ऑल वेदर रोड का

विस्तार सीमान्त क्षेत्र तक किया जाना चाहिए। राज्य के कुमाऊँ मण्डल में टनकपुर से बागेश्वर रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए। सीमित संसाधनों के कारण उत्तराखण्ड राज्य को रेलवे परियोजनाओं के लागत में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी की शर्त पर छूट मिलनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में नैनी सैनी, गौचर, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियां विद्यमान हैं। सामरिक दृष्टि से इनके विस्तारीकरण और अन्य हैलीपोर्ट्स का भी निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। कुमाऊँ एवं गढ़वाल क्षेत्र के मध्य तथा राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के निकट स्थित चौखुटिया क्षेत्र में एक नये एयरपोर्ट की स्थापना किया जाना आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की आपदा के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य को एक सशक्त वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, डॉप्लर रडार से युक्त अवस्थापना तंत्र की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने भारत नेट-2 परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी विहीन 5942 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु भारत नेट-2 परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य शीघ्र स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कैम्पा के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण के खाते में रखे जाने वाली 10 प्रतिशत की धनराशि को घटाकर 2 प्रतिशत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस शेष 8 प्रतिशत धनराशि को राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत कैम्पा में अनुमन्य गतिविधियों के अन्तर्गत वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी जनहित व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमान्त जनपदों के हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। हिम प्रहरी दल द्वारा दैवीय आपदाओं के समय सूचना, राहत एवं बचाव कार्य, ग्राम वासियों को सीमा सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण, जागरूकता, आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने भारत सरकार से इसके लिये आर्थिक सहायता का अनुरोध किया।

महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा अग्निवीर भर्ती में मानकों की हो जांच

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के युवाओं को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वार्ता कर इसकी जांच किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के युवाओं को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौडाय़ा जा रहा है और उसमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। जबकि शारीरिक में पूर्व में औसतन 300

में से 60 का चयन किया जाता था।

महाराज ने कहा कि कोटद्वार में 19 अगस्त 2022 से 31 अगस्त तक बीआरओ लैन्सडाउन अग्निवीरों की भर्ती कर रहा है। भर्ती होने वाले युवाओं का कहना है कि भर्ती के दौरान नियमों की अनदेखी की जा रही है। दौड़ का समय 1600 मीटर के लिये 5:40 सेकन्ड है लेकिन वह सिर्फ 5 मिनट में ही दौड़ को समाप्त कर दे रहे हैं। उतराखण्ड के जवानों के लिए 163 सेन्टीमीटर लम्बाई है जो कि स्वर्गीय पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने उतराखण्ड के लिए करवाई थी। लेकिन भर्ती होने आये युवाओं की हाइट अब 170 सेन्टीमीटर ले रहें हैं।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा कि इस प्रकार की विसंगतियों के चलते उतराखण्ड के बच्चे निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं। इसलिए अग्नीवीर योजना के तहत की जाने वाली इस भर्ती की जांच करवाकर करवाई जाए।

अल्मोड़ा में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अल्मोडा, 22 अगस्त । उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से एक सड़क हादसा की दुखद खबर सामने आए है। बता दे की एक तेज रफ्तार ट्रक ने 7 साल की बच्ची को रौंद दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक संख्या यूके 04 सीबी 2021 जो हल्द्वानी से पाटी की ओर जा रहा था तभी शहर के गेट बाजार इलाके में ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। इस हादसे में मृतक का भाई बाल-बाल बच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

आपको बता दें कि लोडेड ट्रक तेज रफ्तार में था। इस दौरान क्वेटा मचानखान सिटी गेट ट्रक की चपेट में सड़क किनारे दौड़ रही सोनी, 7 साल की बेटी राजन

बजेठा आ गई। जाते जाते लड़की ने किया ऐसा कारनामा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान, ट्रक के रौंदने से पहले सोनी ने अपने साथ जा रहे छोटे भाई को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वह ट्रक की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया। जबकि सोनी खुद ट्रक के टायर और सड़क किनारे लगे पैराफिट में फंस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

UKSSSC कांड : उत्तराखंड के उप नेता सदन भुवन कापड़ी ने सीबीआई जाँच की मांग की

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

खटीमा, 22 अगस्त । खटीमा से विधायक और उत्तराखंड के उप नेता सदन भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग विवाद पर धामी सर्कार से कई मांगे सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के जिम्मेदार लोग आयोग के अध्यक्ष और आयोग के सचिव अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे थे। क्योंकि पेपर की छपने की गोपनीयता की एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष और सचिव की थी उन पर तत्काल प्रभाव से लापरवाही करने के लिए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।

पूरे प्रदेश में परीक्षा कराने वाली एजेंसी की भूमिका भी हर परीक्षा में संदिग्ध है क्योंकि यही कंपनी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा परीक्षाओं में गड़बड़ी

करने के कारण एजेंसी पर प्रतिबंध लगाया गया है और ब्लैक लिस्टेड किया गया था। उत्तर प्रदेश के थाने में उपयुक्त कंपनी पर अभियोग पंजीकृत है ऐसी एजेंसी से उत्तराखंड में परीक्षाएं कराने पर भी ज़िम्मेदार लोगों पर एसटीएफ को अभियोग दर्ज करना चाहिए। सोशल मीडिया पर लगातार जिसको राज्य सरकार द्वारा एसटीएफ द्वारा भर्ती का मुख्य सरगना बताया जा रहा है

उस हाकम सिंह के साथ राज्य के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के कहीं प्रशासन के अधिकारियों के और भाजपा के मंत्री नेताओं के फोटो रोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल निरंतर गिर रहा है क्योंकि एसटीएफ राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है। उसके अधिकार भी राज्य में सीमित है तो आप समझ सकते हैं कि आगे एसटीएफ की जांच किस प्रकार चलेगी। राज्य के एजेंसी होने के कारण उनकी जांच को प्रभावित किया जा सकता है एवं अब पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड 2 राज्यों से जुड़ चुका है लगातार उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारियां हो रही है।

ऐसे में एसटीएफ का दूसरे राज्य में जांच करना संभव नहीं होगा। अतः हम राज्य सरकार से मांग कर मांग करते हैं अगर वह उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित है तो चयन आयोग की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए एवं दोषियों की संपत्तियां जो की भर्ती गड़बड़ी से अर्जित की गई है उनको जबत किया जाए। मुख्य अपराधियों पर रासुका लगा कर प्रदेश में युवाओं के सामने एक नजीर पेश की जाए जिससे कि भविष्य में कोई भी उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार पर डाका ना डाल सके।

BHART PITCH ATHON प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा मौक़ा : चंदन राम दास , कैबिनेट मंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । विधानसभा में मंत्री चंदन राम दास के द्वारा Startup Uttarakhand के तहत BHART PITCH ATHON नाम से 24 अगस्त को रुड़की व 27 अगस्त को अल्मोड़ा में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के पास सुनहरा मौक़ा है, स्टार्टअप की दुनिया के दिग्गजों से मिलने का और उनसे नए चीजे सीखने का अवसर है

आपको यहाँ बता दें कि भारत pitchathon देश के 21 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। ख़ास बात ये भी है कि उत्तराखंड में 1 नहीं 2 जगह pitchathon आयोजित हो रहा है, मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के आयोजन प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित किए जाएंगे।।

सावधान : सड़कों में जमे पानी में हो सकता है करंट

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । उत्तराखंड में बारिश की रफ्तार धीमी तो हुई है, लेकिन कई दिक्कतें दे गई हैं और इस बार उत्तराखंड की बारिश ने काफी नुकसान किया है। बारिश के कारण सड़कों पर पड़े पानी में बच्चों का स्कूल आना -जाना खतरों से खली नहीं। बता दे, एक मामला देहरादून से सामने आया है। जहां सेंट थॉमस स्कूल के पास छुट्टी के दौरान विक्रम में बैठे दो बच्चों की करंट लगने से आस पास के लोग हैरान हो गए दरअसल, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त काफी तेज बारिश हो रही थी।

स्कूल की छुट्टी के बाद जब सेंट थॉमस स्कूल के बच्चे ऑटो में बैठने के लिए पानी में उतरे. तभी एक छात्र को करंट लग गया। किसी तरह उस बच्चे ने खुद को संभाला। वहीं विक्रम में दूसरी तरफ बैठ रही एक और छात्र भी करंट की चपेट में आ गए। वह उसी बिजली के खंभे से

चिपक गई और नीचे पानी में गिर गई। आसपास खड़े लोगों ने कुशलता से इन बच्चों को वहां से निकाला। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। तब तक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

जो शिकायत जनसुनवाई में एक बार आ गई है वह दोबारा न आए : सोनिका डीएम, देहरादून

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें 45 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें अधिकतर शिकायतों संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। तथा शेष शिकायतों को जिलाधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी क्षेत्र में की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले।

जनसुनवाई कार्यक्रम में अतिक्रमण, भूमि कब्जा, भूमि मुआवजा कम मिलने, पेंशन, आय प्रमाण पत्र निर्गत करने, दाखिल खारिज, सीमांकन, सीवर का पानी घरों में घुसने, आन्दोलनकारी चिन्हिकरण, भूमि पट्टा यथावत रखने, सरकारी भूमि पर कब्जा हटवाने, कोविड के दौरान शासकीय सेवाओं में लगे वाहनों का भुगतान दिलाने, पड़ोसियों द्वारा मार-पीट किए जाने, दीवार लगाने, रास्ता रोकने आदि शिकायतें प्राप्त हुई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि

जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जो शिकायत जनसुनवाई में एक बार आ गई है वह दोबारा न आए। उससे पहले ही उसका समाधान हो जाए यदि किसी शिकायत निस्तारण में समय लग रहा है तो शिकायतकर्ता को भी अवगत करा दिया जाए। उन्होंने कलेक्ट्रेट में शिकायत पटल को भी निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का फॉलोअप करते हुए संबंधित विभाग को अनुस्मारक प्रेषित करें।

जनसुनवाई में अपर नगर मजिस्ट्रेट मायादत्त जोशी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज कुमार उप्रेती, जिलाधिकारी के मुख्य व्यैक्तिक सहायक बीरेन्द्र सिंह सहित लोनिवि, नगर निगम, एमडीडीए, समाज कल्याण, राजस्व आदि संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी/कार्मिक उपस्थित रहे तथा उप जिलाधिकारी ऋषिकेश शैलेन्द्र नेगी, चकराता सौरभ असवाल, विकासनगर विनोद कुमार एवं डोईवाला युक्ता मिश्रा वर्चुअल माध्यम से जनसुनवाई में जुड़े रहे।

जाने क्यों होती है जोशीमठ में इतनी भूस्खलन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । जोशीमठ उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहां घूमने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं, सर्दियों में यह जगह स्विट्जरलैंड से काम नहीं लगती। ऐसा कहा जाता है हर अच्छी चीज़ में कोई न कोई बुराई तो जरूर होती है, ऐसा ही जोशीमठ में है। बता दे की जोशीमठ में लगातार भूस्खलन के किस्से आते रहते है जिससे चमोली जिला प्रशासन की चिंता भी बड़ी हुए है, ऐसे में सरकार ने जोशीमठ शहर की जांच के लिए एक टीम भेजी थी। इस तकनीकी टीम में आईआईटी रुड़की, इसरो, जीएसआई, सर्वे ऑफ इंडिया और आपदा प्रबंधन के अधिकारी थे। यह टीम जोशीमठ शहर का निरीक्षण कर लौटी है। जिसमें हमें जोशीमठ शहर में हो रहे भूस्खलन के कारणों के साथ-साथ निरीक्षण के दौरान क्या हुआ, इसके बारे में पता चला।

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भूस्खलन को लेकर अपर सचिव आपदा प्रबंधन जितेंद्र कुमार सोनकर की अध्यक्षता में शोधकर्ताओं की कमेटी गठित की। शोधकर्ताओं की इस टीम में अतिक्रमण विभाग, वाडिया इंस्टीट्यूट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आईआईटी रुड़की और भौगोलिक गतिविधियों से जुड़े अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ता इस समिति में शामिल थे। 16 अगस्त 2022 को शोधकर्ताओं का यह दल तत्काल प्रभाव से जोशीमठ शहर की सतह की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था।

16 अगस्त 2022 को जोशीमठ शहर के निरीक्षण पर गई शोधकर्ताओं की यह टीम कई दिनों तक शोध करने के बाद वापस लौटी है. शोधकर्ताओं की टीम में शामिल उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने ईटीवी इंडिया से बात करते हुए कहा कि जोशीमठ शहर का सतही निरीक्षण शोधकर्ताओं द्वारा विभिन्न मानकों पर किया गया है।

प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में जोशीमठ शहर की इमारतें कुछ सेंटीमीटर नीचे गिर रही हैं। निरीक्षण करने पर पता चला कि घरों में दरारें आ गई हैं। यह स्थिति पूरे शहर में बनी हुई है। वहीं अगर जोशीमठ शहर में हो रहे भूस्खलन के कारणों की बात करें तो शोधकर्ताओं का कहना है कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्तरों पर जांच की गई है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट समिति द्वारा गठित की जाएगी। जोशीमठ शहर में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण शहर में जल निकासी की व्यवस्था का अभाव है।

जिससे बारिश के पानी और सीवरेज की व्यवस्थित निकासी नहीं हो पा रही है। यह पानी धरती के अंदर रिस रहा है। इसके अलावा शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि जोशीमठ शहर में लगातार अंधाधुंध निर्माण हो रहा है, जो शहर के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है।

युद्धस्तर पर राहत पहुंचा रहा देहरादून प्रशासन, लोगों को मिल रही मदद

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न विभागों की टीमें एनडीआरफ, एसडीआरफ, राजस्व, चिकित्सा, वेटनरी, पुलिस विभाग, सिंचाई, जिला पंचायत, लोनिवि, आदि सम्बन्धित विभागों से अधिकारी/कार्मिक आपदा राहत कार्यों लगे हैं तथा जनजीवन को सामान्य लाने में कार्य कर रही हैं तथा क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही शिविर भी लगाया गया है जहां पर राहत सामग्री वितरित की जा रही है, कच्चा राशन, गैस सिलेण्डर-चूल्हा, महिला, पुरूष तथा बच्चों के कपड़े, फोल्डिंग पलंग, गद्दे आदि प्रभावितों को वितरित की जा रही है, जो लोग शिविर तक नहीं आ पा रहे उनको पका हुआ भोजन पंहुचाया जा रहा है। साथ ही मकान, कृषि भूमि, फसल नुकशान का आंकलन कर अहैतुक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सभी अधिकारियों को युद्धस्तर पर कार्य करते हुए जनजीवन को सामान्य बनाने के निर्देश दिए गए है।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में चिकित्सा टीम तैनात रखने तथा रेस्क्यू आपरेशन के दौरान शव बरामद होने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत पोस्टमार्टम टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मौके पर ही पोस्टमार्टम करते हुए पंचनामा आदि कार्यवाही सम्पादित की जा सके ताकि परिजनों को अनावश्यक न भटकना पड़े।

जनपद में विगत शुक्रवार को हुई अतिवृष्टि के चलते आयी आपदा से सरखेत व अन्य क्षेत्रों मे जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है । जिलाधिकारी सोनिका के दिशा निर्देशों पर सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी के. के. मिश्रा तथा शिव कुमार बरनवाल के नेतृत्व में क्षेत्र में राहत एवं बचाव अभियान निरंतर संचालित किया गया जा रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पेयजल, भोजन तथा अन्य राहत सामग्री वितरित की जा रही हैं।

भेंसवाड़ा/सरखेत में खोज-बचाव कार्य गतिमान है वर्तमान में 07 लोग लापता है, जिनकी खोजबीन की जा रही है 03 घायल व्यक्तियों का उपचार मैक्स तथा 02 घायलों का उपचार हिमालयन हास्पिटल में चल रहा है। प्रभावित क्षेत्र में वर्तमान मे 16 प्रभावित परिवारों को जूनियर हाईस्कूल मालदेवता में शिफ्ट किया गया है, जिनके खाने एवं अन्य व्यवस्था जिला प्रशासन एवं जिला पूर्ति विभाग के माध्यम से की जा रही है।

एससीपी के अन्तर्गत किये गए कार्यों की सूची राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने तलब की

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर 22 अगस्त। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति से संबंधित विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकरणों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर मिले, ऐसे नागरिक जो योजना की पात्रता रखते है लेकिन जानकारी के अभाव में दस्तावेज तैयार नहीं कर पाते, अधिकारी स्वप्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित करें।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग में जो प्रावधान किए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभांवित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति के कल्याण तथा लोगों की समस्याओं के निस्तारण के प्रति पूर्ण संवेदनशील होकर कार्य करें तथा उन्हें लाभांवित करते हुए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मददगार बनें।

उन्होंने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि अटल आवास योजना में धनराशि कम होने के कारण अटल आवास योजना के स्थान पर पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभांवित कराया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम सभा की खुली बैठकों का रोस्टर जारी करते हुए खुली बैठकों का अधिक से अधिक प्रचार किया जाये और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के पात्रों व विकासपरक योजनाओं का चुनाव खुली बैठकों में ही किया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि एससीपी मद की धनराशि का उपयोग जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि एससीपी के अन्तर्गत जो भी कार्य किये जाये उनकी सूची आयोग को भी उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने सहकारित तथा उद्यान विभाग को आपसी तालमेल से कार्य करने के भी निर्देश दिये।

एमवे इंडिया 100 प्रतिशत प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बना

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । देश में एमवे इंडिया अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संग्रहण के आधार पर 100 प्रतिशत पोस्ट-कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट का प्रबंधन करने और एमवे विनिर्माण सुविधा में उत्पन्न 100 प्रतिशत प्री-कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल करने के बाद प्री और पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है।

कंपनी ने 800 मीट्रिक टन पोस्ट-कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट संग्रह और रिसाइकल किया है, जो 5 करोड़ यूनिट से अधिक प्लास्टिक प्रोडक्ट वेस्ट के प्रबंधन के बराबर है जिसमें विभिन्न आकार की बोतलें, ट्यूबें, कैप, जार और पाउच शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसने प्री-प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए अपने विनिर्माण संयंत्र में 100 प्रतिशत खतरनाक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल और फिर से इस्तेमाल किया है। पर्यावरण और समाज संबंधी समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण के जरिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने अपनी संवहनीयता महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ स्पष्ट कदम उठाए हैं, जिससे लोगों की बेहतर जीवन, स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने की अपनी दृष्टि को फिर से बहाल किया है।

इस मौके पर एमवे इंडिया के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स, आदिप रॉय ने कहा, "एमवे में, स्वस्थ धरती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे प्रोडक्ट्स, प्रक्रियाओं और फिलॉसफी में परिलक्षित होती है। संवहनीयता केवल अनुपालन से नहीं जुड़ी है बल्कि एमवे की संस्कृति का अंतर्निहित हिस्सा है। प्री और प्रोस्ट-कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रलिटी हासिल करना हमारी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, एमवे इंडिया प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) में पंजीकरण कराने वाले देश के पहले ब्रांड स्वामियों में से एक है।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदसन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया है। उनका बस इतना कहना है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से सरकार को इस मामले पर ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने पेपर लीक मामले में आरोपियों को संरक्षण देने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। वह सरकार, आयोग एवं आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं हाथों में युवाओं से धोखा जैसे पोस्टर लेकर बैठे है। इस दौरान गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद, कमलेश रमन, आजाद अली, उमा सिसोदिया आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड कांग्रेस ने छोड़ा, एसडीएम के खिलाफ मौन का बाण

देहरादून, 22 अगस्त । हाल ही में एक वीडियो वायरल होती दिखाई दे रही थी, जिसमें पौड़ी में यूथ कांग्रेस महासचिव नितिन बिष्ट के साथ उत्पीड़न होती दिखाई दे रही थी। ये विवाद यूथ कांग्रेस महासचिव नितिन बिष्ट और एसडीएम के बीच का है। जिसके विरोध के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क में एक घंटे के मौन पर बैठ गए।

पूर्व सीएम हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा एसडीएम एक लोक सेवक है। उससे इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नहीं जाती। इसका हम विरोध कर रहे है ताकि आगे ऐसा किसी के साथ ना हो। आपको पूरी घटना के बारे में बता दें कि नितिन बिष्ट सर्टिफिकेट को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर ही एसडीएम के पास गए थे। समस्या का समाधान करने की बजाय गाली गलौज की गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार एसडीएम के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और बेलगाम नौकरशाही को कड़ा संदेश दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस विरोध करती रहेगी।

जानिए उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के नए नियमों के बारे में

देहरादून, 22 अगस्त । आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के 225 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इसमें 102 सरकारी और 123 निजी अस्पताल शामिल हैं। प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों, 39 एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों और पहाड़ी क्षेत्रों के सात निजी अस्पतालों में इलाज के लिए रेफरल सिस्टम लागू नहीं होगा. मरीज को इलाज के लिए 74 निजी अस्पतालों में रेफर करना अनिवार्य है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अटल आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख की सीमा तक मुफ्त इलाज के लिए रेफरल प्रणाली को सख्ती से लागू किया है। योजना में सूचीबद्ध 74 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पहले मरीज को सरकारी अस्पताल से रेफर करना अनिवार्य है। आपात स्थिति में रेफरल सिस्टम लागू नहीं होगा।

प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने आईटी पार्क कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए रेफरल नीति बनाई है. इसके पीछे मंशा यह है कि आयुष्मान कार्ड धारक मरीज का इलाज पहले राज्य के अस्पतालों में किया जाए। इलाज की सुविधा न होने पर ही निजी अस्पतालों में रेफर करने की व्यवस्था है। सरकार ने कोविड महामारी में इस व्यवस्था में ढील दी थी। अब फिर से मरीज का बायोमेट्रिक और रेफरल सिस्टम लागू कर दिया गया है।

प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि कई सरकारी अस्पतालों में कार्ड धारक मरीजों को बिना किसी कारण के सीधे निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इस देखते हुए प्राधिकरण ने तय किया कि सरकारी अस्पतालों को मरीज रेफर करने का स्पष्ट कारण बताना होगा। यदि अस्पताल में उपचार की सुविधा नहीं है तो मरीज किसी अन्य दूसरे राजकीय चिकित्सालय में रेफर किया जाना चाहिए। वहां पर इलाज संभव नहीं है तो ही निजी अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। कोटिया ने बताया कि इमरजेंसी की स्थिति में रेफर करने की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इस मौके पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ एवं अपर सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद थे।

संपादकीय

दक्षिण में बदलते सियासी हालात

छह दक्षिणी राज्यों- तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी में अलग-अलग पार्टियां सत्ता में हैं. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिन पार्टियों- कांग्रेस, डीएमके, टीआरएस, सीपीएम ने विजयी उम्मीदवारों का समर्थन नहीं किया, उन्हें बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. राहुल गांधी पर इनकी निर्भरता भी अचरज की बात है और उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार भी इन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक धक्का है. कांग्रेस भी लगातार कमजोर हो रही है. दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रीय दल श्रीलंका में रुके चीन के खुफिया जहाज की जासूसी से संरक्षण चाहते हैं. विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने या तो केंद्र को पत्र लिखा है या केंद्रीय नेताओं से मिलकर इसरो, कुडनकुलम संयंत्र, कोच्चि बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी में तैनात परमाणु पनडुब्बियों जैसे स्थानों की चीनी जासूसी पर विरोध जताया है. अगर श्रीलंका में संकट बना रहता है, तो शरणार्थियों की समस्या आ सकती है तथा प्रतिबंधित लिट्टे जैसे संगठनों के अतिवादी व समर्थक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बंदरगाहों तक नाव से पहुंच सकते हैं. दक्षिणी राज्यों के मतदाताओं ने छह पार्टियों को ताकतवर जरूर बनाया है, पर वे सभी केंद्र सरकार के निकट आना चाहते हैं, ताकि उनके राज्यों को आर्थिक पैकेज, अतिरिक्त अनुदान, परियोजनाओं के लिए मदद मिल सके. जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चुने गये, तो दक्षिणी राज्यों में भाजपा के प्रति धारणा में व्यापक बदलाव आया. उस जनादेश से यह संकेत गया कि हिंदी पट्टी में मोदी-योगी डबल इंजन के असर को तोड़ा नहीं जा सकता. इससे दक्षिण के मतदाताओं का रूझान भी बदल रहा है. चार पार्टियां- डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, सीपीएम और टीआरएस नरेंद्र मोदी और भाजपा का जम कर विरोध करते हैं. इन दलों को लगता था कि भाजपा उत्तर प्रदेश हार जायेगी और 2024 में विरोधी दलों को जनादेश मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किये जा रहे डिजिटल बदलाव, कोरोना महामारी का बहुत अच्छा प्रबंधन, मोदी शासन में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं होना जैसे कारकों से युवाओं की सोच बदलने लगी है. क्षेत्रीय दल 2023 गुजरने के इंतजार में है. तब तक दक्षिण के मुख्यमंत्री मोदी के करीब दिखना चाहते हैं. कभी स्टालिन की पार्टी डीएमके ने काले झंडों और गुब्बारों से मोदी का विरोध किया था तथा उत्तर भारतीय विरोधी माहौल बनाया था, पर उत्तर प्रदेश के नतीजे के बाद यह सब बदल गया. स्टालिन ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए चार दिन दिल्ली रहे, पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. लगभग सभी क्षेत्रीय दलों ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभद्र भाषा बोलना कम कर दिया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने हाल में कहा कि उनकी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से नहीं डिगेगी तथा किसी भी हाल में भाजपा और आरएसएस से समझौता नहीं करेगी. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री होने के नाते विकास योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं. इसे डीएमके और भाजपा के बीच संबंध नहीं समझा जाना चाहिए. इस माह वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दो बार प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं.

20 हज़ार लोगों को खाना खिलाएंगे सतपाल महाराज, 1000 कंबल भी भेजे

महाराज ने जागड़ा में 20 हजार लोगों के भण्डारे को भिजवाई खाद्य सामग्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 22 अगस्त। प्रदेश के पर्यटन , धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने हनोल स्थित जागड़ा मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ-साथ इस दौरान होने वाले भंडारे के लिए अपनी ओर से खाद्य सामग्री भी मंदिर समिति को भिजवाई है। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने हनोल में 30-31अगस्त 2022 को होने वाले जागड़ा मेले के भव्य इंतजाम करने और मंदिर को फूलों से सजाने के एसडीएम सौरव असवाल को निर्देश दिए हैं।

मेले की व्यवस्थाओं के साथ-साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुचारू बस सेवा संचालन हेतु महाराज ने जहाँ एक ओर प्रदेश में हनोल पहुँचने के लिए बसों की व्यवस्था की बात कही है वहीं उन्होने हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह से हिमाचल से हनोल आने वाले लोगों के लिए शिमला से भी बस की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

जागड़ा महोत्सव में देवता के दरबार में रात्रि जागरण के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं और पूरी रात लोक नृत्य के माध्यम से महासू देवता की स्तुति करते हैं। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जागड़ा के दौरान होने वाले भंडारे के लिए अपनी ओर से 20 हजार लोगों के लिए खाद्य सामग्री और 1000 कंबल भी मंदिर समिति को दिए हैं।

सरखेत आपदा प्रभावित के 18 परिवारों को मंत्री गणेश जोशी ने बांटी राहत राशि

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 22 अगस्त। अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी सरखेत पहुंचे। जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत आपदा प्रभावित के 18 परिवारों को धनराशि एक लाख पांच हजार सात सौ रुपए के राहत राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान आपदा प्रभावित ग्रामीणों ने मंत्री जोशी के सामने ने विस्थापन की गुहार लगाईए जिस पर काबीना मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावितों को शीघ्र विस्थापन का भरोसा दिलाया और कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार इस दुःख की घड़ी में प्रभावितों के साथ हर पल खड़ी है।

आपदा के तीसरे दिन भी अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर सरखेत आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोशी ने पूर्णनिर्माण और राहत बचाव कार्यों की अधिकारियों से जानकारी भी ली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने प्रभावितों को भोजनए पानीए रहने आदि की दिक्कत न हो इसके लिए मौके पर मौजूद प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार प्रशासन की ओर से टूटे सड़क मार्गों और बिजली का कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा हैए लापता लोगों का सर्च ऑपरेशन भी युद्ध स्तर जारी है।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, अनुज कौषल, बालम सिंह, तहसीलदार सोहन सिंह राणा, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल, परियोजना निदेशक आरके तिवारी, बीडीओ चक्रधर सेमवाल सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

सतपाल महाराज के बयान ने दिया कांग्रेस को हमले का मौका

- महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री भट्ट को लिखा शिकायती पत्र
- केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय उत्तराखंड में हो रही अग्निवीरों कि भर्ती ने की जा रही धांधली पर कार्यवाही करें-धस्माना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त। गढ़वाल में अग्निपथ योजना के तहत चल रही अग्निवीरों कि भर्ती प्रक्रिया पहले से ही युवाओं में आक्रोश पैदा कर रही थी अब इस पर राज्य के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज के ताजा बयान ने आग में घी का काम कर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केंद्र की भाजपा सरकार को हमले का मौका दे दिया है। महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को पत्र लिख कर बीआरओ लेंसिडाउन पर धांधली का आरोप लगाते हुए लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी करते हुए 300 लोग दौड़ाए जा रहे हैं उनके अनुपात में भर्ती केवल 8 से 10 युवाओं को किया जा रहा है जबकि पहले 50 से 60 युवाओं को नियमित भर्ती में चयनित किया जाता था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कद के मामले में भी 167 सेंटीमीटर की जगह 170 सेंटीमीटर लिया जा रहा है जो गलत है। सतपाल महाराज के पत्र में लगाये आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना ने कहा कि जो आरोप प्रदेश के युवा लगा रहे हैं और जिस विषय पर युवा कांग्रेस के साथी विरोध प्रकट कर रहे हैं उन आरोपों पर अब स्वयं राज्य के वरिष्ठ मंत्री ने मोहर लगा दी है।

कांग्रेस लीडर धस्माना ने कहा कि पहले ही अग्निपथ योजना सेना विरोधी युवा विरोधी है और अब तो इस विनाशकारी नीति में भी महाविनाशकारी धांधली की जा रही है जो करेला उस पर नीम चढ़ा की कहावत की चिरथार्थ कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को व रक्षा मंत्रालय को तत्काल इस पर कार्यवाही करनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए।

गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया राष्ट्रीय सुरक्षा का मोदी विजन

मो0 सलीम सैफ़ी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 22 अगस्त। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। मौजूदा एवं उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री की संकल्पनाओं पर आधारित विभिन्न पहलों को भी इस दौरान सामने रखा है।

2. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 से डीजीपी सम्मेलन का स्वरूप बदलने का प्रयास किया है और इसका विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि कई समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।

3. सभी राज्यों को चाहिए कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को शीर्ष प्राथमिकता दें, ये देश और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है जिसके लिए हमें एक दिशा में एक साथ लड़कर हर हालत में जीतना है।

4. गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों के DGPs सीमा क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफिक परिवर्तन पर सजग निगरानी रखें।

5. राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने राज्यों में, विशेषकर सीमांत ज़िलों में, सभी तकनीकी और रणनीतिक महत्व की जानकारियां नीचे तक पहुंचाएं।

6. 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेन्द्र मोदी ने न सिर्फ़ देश की आंतरिक सुरक्षा पर थ्रस्ट दिया, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए तंत्र को भी मज़बूत किया।

7. आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, उत्तर-पूर्व में विभिन्न उग्रवादी गुटों और वामपंथी उग्रवाद के रूप में जो तीन नासूर थे, उन्हें ख़त्म करने की दिशा में हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने कई नए कानून बनाए, राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया, बजटीय आवंटन बढ़ाया और तकनीक का अधिकतम उपयोग किया।

8. राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) के रूप में देश में पहली बार एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है, हमें इसे निचले स्तर तक परकोलेट करना चाहिए।

9. सिर्फ कन्साइनमेन्ट को पकड़ना काफी नहीं है, ड्रग्स के नेटवर्क को समूल उखाड़ना और इसके स्रोत और डेस्टिनेशन की तह तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है।

10. हर राज्य के अच्छे इन्वेस्टिगेटिड केसेस की हमें डिटेल्ड अनालिसिस करनी चाहिए।

11. NCORD की ज़िलास्तरीय नियमित बैठकें सुनिश्चित की जानी चाहिए और इनका उपयोग नीचे तक पहुंचाना चाहिए।

12. प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरूआत की है लेकिन वो सफल तभी होगा जब हम इसे नीचे तक पहुंचा पाएंगे।

13. केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकार के अपराधों का डाटाबेस तैयार कर रही है...देश में पहली बार साइंटिफिक अप्रोच के साथ इतने सारे मोर्चों पर एक साथ इतना काम हुआ है।

14. सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने के लिए हमें 5जी तकनीक का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा।

15. आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसी का आधारभूत सिद्धांत ₹Need to know₹ नहीं, बल्कि "Need To Share" एवं ₹Duty To Share₹ होना चाहिए क्योंकि जब तक अप्रोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी।

16. तकनीक के साथ-साथ हमें ह्यूमन इंटेलीजेंस के उपयोग पर भी बराबर थ्रस्ट देना चाहिए।

17. ये सम्मेलन युवा अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गहरी जानकारी देने में मदद करता है।

18. विगत दो दिनों में विचार-विमर्श के लिए चुने गए सत्र प्रासंगिक और महत्वपूर्ण थे और इन दो दिनों में हमने निम्न विभिन्न विषयों पर चर्चा की:

i. काउंटर टेरर एवं काउंटर रेडिकलाइजेशन
ii. माओवादी ओवरग्राउंड एवं फ्रंट आर्गेनाईजेशन की चुनौतियाँ
iii. क्रिप्टो करेंसी
iv. काउंटर ड्रोन तकनीक
v. साइबर और सोशल मीडिया पर निगरानी
vi. द्वीपों, बंदरगाहों की सुरक्षा vii. 5G टेक्नोलॉजी के चलते उभरती चुनौतियाँ
viii. सीमा क्षेत्रों पर डेमोग्राफिक परिवर्तन एवं बढती कट्टरता
ix. नशीले पदार्थों की तस्करी

19. प्रतिनिधियों ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। Specialized fields के Cutting edge level के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भी अपने सुझाव दिए। माननीय गृह मंत्री ने प्रस्तावित समाधानों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने की बात कही।

20. सम्मेलन में अजय कुमार मिश्रा गृह राज्यमंत्री, निशीथ प्रामाणिक, गृह राज्यमंत्री, CAPFs, CPOs और विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के प्रमुखों तथा राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया।

"मंहगाई पर हल्ला बोल" महारैली में उत्तराखंड कांग्रेस दिखाएगी ताक़त : यशपाल आर्य

अध्यक्ष करन माहरा ने तैयार की रणनीति , दिए निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 22 अगस्त । देशभर में आसमान छूती मंहगाई, बढती बेरोजगारी एवं मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दिनांक 4 सितम्बर, 2022 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली ''मंहगाई पर हल्ला बोल'' महारैली की तैयारी हेतु से जुडी बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के जिला, शहर अध्यक्षों, अनुषांगिक संगठन, विभाग एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की आयोजित हुई।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने को आम आदमी से सम्बद्ध करते हुए उसके हकों की लडाई के लिए 4 सितम्बर, 2022 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ''मंहगाई पर हल्ला बोल'' महारैली का आयोजन किया है इसकी तैयारी हेतु आज प्रदेश अध्यक्ष श्री करन माहरा जी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कांग्रेसजनों से बडी संख्या में दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए कहा कि आज देश में मंहगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, गरीब को दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड रहा है वहीं दूसरी ओर देश में बेरोजगारी महामारी की भांति पैर पसार चुकी है। ऊपर से केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा आम आदमी की आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर जनता की कमर तोडने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सदैव गरीब के साथ खडी रही है तथा उसकी जरूरतों को महसूस करती है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार बढती मंहगाई व बेरोजगारी के खिलाफ 4 सितम्बर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ''मंहगाई पर हल्ला बोल'' महारैली का आयोजन किया है जिसमें उत्तराखण्ड राज्य से अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रतिभाग करना है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में जिला, महानगर, ब्लाक व नगर स्तर पर मुख्य सार्वजनिक स्थानों में चैपाल के माध्यम से ''मंहगाई पर चर्चा'' कार्यक्रम आयोजित कर जनता को भाजपा सरकार की नाकामियों से अवगत कराने के साथ ही आसमान छूती मंहगाई से आम आदमी की पहुंच से दूर होती जरूरी सामान की कमीतों, सुरसा के मुंह की भांति बढ़ती बेरोजगारी तथा मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाने का काम करेगी तथा आम जनता से इन बिन्दुओं पर चर्चा करेगी।प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, राजीव भवन में 4 सितंबर को रामलीला मैदान, दिल्ली में महंगाई के विरोध में होने वाली मंहगाई पर हल्ला बोल महारैली की तैयारी बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, विधायक रवि बहादुर, राजेंद्र भंडारी, विक्रम नेगी, श्री गोपाल राणा, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, ललित फरस्वान, मनोज रावत, जयेंद्र रमोला,एआईसीसी सदस्य चमन सिंह, संजय पालीवाल, गरिमा दसोनी, महेश शर्मा, धीरेन्द्र प्रताप, सरोजनी कैन्तूरा, पी.के. अग्रवाल, अमरजीत सिंह, आदि उपस्थित थे।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा